भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1934
उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति

1934# **श्री महेंद्र भट्टः**
क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति**,** 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अब तक कौन-कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं**;** और
(ख) शिक्षकों के प्रशिक्षण**,** कौशल विकास और स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, अधिगम के परिणामों में सुधार करना, समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना और बच्चों के समग्र विकास का संवर्धन करना, सुनिश्चितकरके स्कूल शिक्षा प्रणाली को बदलना है।

एनईपी 2020 की घोषणा के बाद कई कदम उठाए गए हैं जैसे एनईपी, 2020 की सिफारिश के साथ की केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा का अनुकूलन; ग्रेड 2 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्याज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) का शुभारंभ; तीन महीने के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या-प्रवेश दिशानिर्देश; शिक्षा के लिए सुसंगत मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए पीएम ई-विद्या; ई-पुस्तकें और ई-सामग्री वाले एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा (ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना); 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों

के लिए तैयार की गई खेल-आधारित शिक्षण शिक्षण सामग्री के लिए बुनियादी स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और जादुई पिटारा का शुभारंभ; माध्यमिक स्तर तक की संपूर्ण शैक्षिक यात्रा को पूरा करने के लिए स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई)। अन्य पहलों में परख (समग्र विकास के ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना शामिल है; निष्ठा (स्कूल प्रमुख और शिक्षकों के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय पहल), बुनियादी साक्षारता और संख्याज्ञान(एफएलएन) और प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई); विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी); शिक्षा पारिस्थितिकी को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा निर्माण हेतु राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर) ,15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों को लक्षित करते हुए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम / अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग इन सोसाइटी (यूएलएएलएएस) का शुभारंभ।

प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम एसएचआरआई) योजना के तहत 13092 स्कूलों को अनुकरणीय स्कूलों के रूप में चुना गया है, जिसमें उत्तराखंड के 241 स्कूल शामिल हैं, जो एनईपी 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करते हुए पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हैं।

चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में हैं इसलिए निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन करते हुए एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों और उत्तराखंड सहित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आती है ।

उत्तराखंड राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें की गई हैं:

- निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुसार मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल "आरोही" कक्षा I में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए विकसित किया गया है और इसे सभी सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है। प्रगति ऐप के माध्यम से एफएलएन के तहत छात्रों की प्रगति की लगातार निगरानी की जा रही है।

- बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 (एससीएफ-एफएस) के अनुरूप, बुनियादी स्तर के लिए राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा (एससीएफ-एफएस) 11 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया है। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय/एनसीईआरटी द्वारा जारी स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2023 (एनसीएफ-एसई) के आधार पर, स्कूल शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा (एससीएफ-एसई) भी विकसित और शुरू की गई है।
- बैगलेस डेज के कार्यान्वयन के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए हैं और एक गतिविधि पुस्तिका विकसित की गई है। राज्य ने एनईपी, 2020 के अनुसार कक्षा I में प्रवेश के लिए संशोधित आयु निर्धारण मानदंड लागू किए हैं।
- राज्य ने सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की पहचान की है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 486 विशेष शिक्षा जोन (एसईजेड) अधिसूचित किए हैं।

उत्तराखंड राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है -

- समग्र शिक्षा के तहत, एनईपी, 2020 के अनुरूप आवश्यकता-आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 47,020 शिक्षकों ने एआई और आईसीटी-सक्षम कौशल विकास के लिए एमओओसी (10 घंटे के एमओओसी 1.0 और 20 घंटे के एमओओसी 2.0) को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जबकि 11,994 शिक्षकों ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से 21वीं सदी के कौशल संबंधी एमओओसी पाठ्यक्रम पूरा किया है।
- निष्ठा 3.0 के तहत 25,644 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 22,944 शिक्षकों ने मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर, 2,545 शिक्षकों ने आईसीटी-आधारित कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- माध्यमिक स्तर पर निष्ठा 2.0 के तहत 26,214 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, और 2,756 सेवारत शिक्षकों को भी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

- इसके अलावा, सरकारी स्कूलों के 22,083 शिक्षकों ने एनईपी के अनुरूप विभिन्न विषयों के संबंध में सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उद्यमशीलता के विचार को विकसित करने के लिए कौशलम पाठ्यक्रम के तहत 1,170 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, और एसटीईएम शिक्षा के तहत 2,456 गणित और विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

मातृभाषाओं और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोक कलाओं और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर भी विशेष बल दिया गया है। उत्तराखंड राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार मातृभाषाओं, स्थानीय भाषाओं, लोक कलाओं और स्थानीय संस्कृति के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल स्तर से राज्य स्तर तक मातृभाषा उत्सव का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें विकसित की गई हैं, एनसीईआरटी बरखा श्रृंखला की पुस्तकों का गढ़वाली और कुमाऊंनी में अनुवाद शुरू किया गया है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने खिलौना आधारित शिक्षाशास्त्र के उद्देश्य से जादुई पिटारा को अनुकूलित/प्रासंगिक बनाया है।

******